राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता ■ कर्त्तव्य ■ समर्पण

■ लखनऊ ■ नई दिल्ली ■ गोरखपुर ■ पटना
■ कानपुर ■ देहरादून ■ वाराणसी से प्रकाशित

लखनऊ
मंगलवार ● 23 अक्टूबर ● 2018
पृष्ठ 18, मूल्य ` 3.00

# प्रदेश के शहरों में सीवर प्रबंधन की हालत खस्ता

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

**लखनऊ।**

प्रदेश के शहरों में सीवरेज प्रबंधन की हालत खस्ता है। सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड इन्वाइरनमेंट (सीएसई) के हालिया अध्ययन में शहरों के सीवरेज प्रबंधन की कलई खोल दी है। यही नहीं जेएनएनयूआरएम जैसी योजनाओं में अब तक खर्च हुई करोड़ों की धनराशि की उपयोगिता पर भी सवाल उठे हैं।

**सीएसई के हालिया अध्ययन में शहरों के सीवरेज प्रबंधन की खुली कलई**

**जेएनएनयूआरएम जैसी योजनाओं में खर्च हुए करोड़ों रु. की उपयोगिता पर भी उठे सवाल**

सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सेप्टिक टैंक (47 प्रतिशत) जैसे ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली वाले परिवार हैं। सीवर कनेक्शन (28 प्रतिशत) से अधिक है। राज्य वार्षिक कार्य योजना 2017-20 के अनुसार, अधिकांश शहरों ने शौचालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कवरेज की सूचना दी है, लेकिन 60 एएमआरयूटी (अमृत) शहरों में से 34 ने सीवरेज के संग्रह और उपचार के संबंध में शून्य दक्षता की सूचना दी है। राज्य में अधिकांश घर, संस्थान, वाणिज्यिक क्षेत्र और सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालय सेप्टिक टैंक और गड्ढे शौचालय जैसे ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर करते हैं।

सीएसई के जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन कार्यक्रम निदेशक सरेश रोहिल्ला ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सीवरेज का 86.73 प्रतिशत या तो जल में फेंका जा रहा है या फिर खाली भूमि या घरेलू पर्यावरण में निपटाया जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में बनाए जाने वाले शौचालयों व ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर इसका वैज्ञानिक और स्थायी समाधान नहीं निकला तो इन नए शौचालयों का उत्पादन करने वाला फिकल(कीचड़) की मात्रा बड़ी समस्या बनेगी।

**शहरों में सीवरेज प्रबंधन ध्वस्त :** सीएसई ने राज्य के 30 शहरों का विश्लेषण किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लगभग 44 प्रतिशत आबादी केंद्रीकृत सीवरेज सिस्टम पर निर्भर है, लेकिन केवल 28 प्रतिशत अपशिष्ट जल का ही सुरक्षित निस्तारण होता है। आबादी का 39 प्रतिशत सेप्टिक टैंक और गड्ढे जैसे ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों पर निर्भर है। 5-10 लाख के बीच की आबादी के शहरों में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी खुली नालियों से जुड़े टैंकों पर निर्भर है। उनमें से लगभग आधा सेप्टिक टैंक के रूप में जाने योग्य है।

अनुसूचित डिस्क्लेमेनेशन की अनुपस्थिति में पैदा हुए कीचड़ का केवल 30 प्रतिशत खाली हो जाता है बाकी टैंक में बनी हुई है और टैंक की उपचार दक्षता को कम कर देती है।

टैंकों को मैनुअल खाली किया जाता है। 1.2-5 लाख के बीच की आबादी के शहरों में 60 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खुली नालियों से जुड़े टैंकों पर निर्भर है। उनमें से 28 प्रतिशत सेप्टिक टैंक के रूप में जाने के योग्य है। 1.2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 60 प्रतिशत से अधिक आबादी खुली नालियों से जुड़े टैंकों पर निर्भर है और उनमें से लगभग आधा सेप्टिक टैंक के रूप में जाना जाने योग्य है।

**उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वच्छता का काम अभियान :** प्रदेश के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में इस कार्य की गति में और तेजी लाई जा रही है और जल्द ही पूरा प्रदेश ओडीएफ (खुले में शौचमुक्त) हो जाएगा। सीएसई ने 'फोरम ऑफ सिटीज जो सेप्टेज प्रबंधित' के लॉन्च की भी घोषणा की और प्रभावी फिकल प्रबंधन की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए दो वेब-आधारित उपकरण जारी किए। श्री सिंह ने सोमवार को क्लार्क अवध में सीएसई द्वारा आयोजित कार्यशाला में कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शहरों में सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सीएसई की महानिदेशक सुनिता नारायण ने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा स्वच्छता प्रबंधन कार्य और इसकी व्यापकता इस संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।